

## मार्च 2024

### PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **चुनाव**
  - लोकसभा और चार राज्यों की वधानसभाओं का चुनाव कार्यक्रम
  - एक साथ चुनाव कराने की सफ़ारिश
- **कानून एवं न्याय**
  - वधायिका के अंदर वोट या भाषण के लिये रशिवत लेने पर वधायकों को मल्लि छूट को समाप्त कया
- **गृह मामले**
  - नागरककता नयमों में संशोधन अधसूचकतक
- **कॉरपोरेट मामले**
  - भारतीय प्रतसिप्ररुद्धा आयोग ने प्रतबिद्धता और नपिटान नयमों को अधसूचकतक कया
- **वतकत**
  - स्व-नयामक संगठनों हेतु रूपरखा
  - बीमा उत्पादों के लयक वननयम अधसूचकतक
  - सूचकांक प्रदाताओं के लयक नयम
  - लघु और मध्यम REIT के लयक रूपरखा
- **उद्योग**
  - इलेक्ट्रकक वाहनों के घरेलू वनररमाण को बद्धावा देने कक योजना
  - इलेक्ट्रकक मोबलकककक प्रमोशन योजना
- **पर्यावरण**
  - प्लास्टकक अपशषकक प्रबंधन नयम, 2016
  - बैटरी अपशषकक प्रबंधन नयम, 2022
- **स्वास्थय**
  - उन्नयन सहायता योजना
- **नवीन एवं अकषय ऊर्जा**
  - राषट्रीय हरकक हाइड्रोजन मशकन
- **वाणककक**
  - उत्तर पूरव परवरकनकारी औद्योगीकरण योजना
  - यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हसुताकषर
- **कोयला**
  - अंतर-मंत्रालयी समककककने कोयला आयात प्रतसकथापन पर रपोरककक जारी कक

## चुनाव

### लोकसभा और चार राज्यों की वधानसभाओं का चुनाव कार्यक्रम

- **भारत का नररवाचन आयोग** ने लोकसभा के आम चुनाव और चार राज्य वधानसभाओं के चुनावों के कार्यक्रमों कक घोषणा कक।
  - **लोकसभा** चुनाव 19 अपरैल, 2024 से 1 जून, 2024 तक सात चरणों में होंगे।
  - वोटों कक गनककती 4 जून, 2024 को होगी।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडककशा और सककककक कक **वधानसभाओं** के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे।

## एक साथ चुनाव कराने की सफ़ारिश

- केंद्र सरकार द्वारा गठित **उच्च स्तरीय समिति** ने एक साथ चुनाव पर अपनी रपॉर्ट प्रस्तुत की।
- इसकी संदर्भ की शर्तों में व्यवहार्यता की जाँच करना और एक ही समय में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिये एक रूपरेखा का सुझाव देना शामिल था।
- समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिन्लखिति शामिल हैं:
  - एक साथ चुनाव का औचित्य**
    - एक साथ चुनाव **आदर्श आचार संहिता** के लागू होने के कारण होने वाले व्यवधान और नीतगित गतहिनीता को कम करके शासन में स्थिरता तथा पूर्वानुमान सुनिश्चित करेंगे।
    - एक साथ चुनाव से लागत कम करने और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
    - एक साथ चुनाव से उच्च आर्थिक विकास, कम मुद्रास्फीति, निवेश में वृद्धि और सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
  - एक साथ चुनाव का कार्यान्वयन:**
    - लोकसभा** के अगले आम चुनाव के समय, एकमुश्त उपाय के रूप में शेष कार्यकाल की परवाह किये बिना, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों को भंग कर दिया जाना चाहिये। इससे सभी चुनाव एक साथ हो जाएंगे।
    - समिति ने लोकसभा और सभी **राज्य विधानसभाओं** के चुनाव एक ही समय पर तथा इन चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सफ़ारिश की।
    - मध्यावधि चुनाव की स्थिति में कम अवधि के लिये नए सत्र से चुनाव कराए जाने चाहिये। घटा हुआ कार्यकाल अगले एक साथ चुनाव तक पाँच साल के चक्र की शेष अवधि के बराबर होगा।

## कानून एवं न्याय

### वधायिका के अंदर वोट या भाषण के लिये रशिवत लेने पर वधायकों को मली छूट को समाप्त कयिा

- संवधान संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों (MLA/MLC) को वधायिका में उनके भाषणों तथा वोटों के लिये आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्रदान करता है (अनुच्छेद 105 और 194 के तहत)।
- वर्ष 1998 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने संसद में अवशिवास प्रस्ताव पर वोट के लिये सांसदों को रशिवत देने के एक मामले की सुनवाई की। उन्होंने **अनुच्छेद 105(2)** के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्रापत है।
  - तर्क यह था कि रशिवत लेना और वोट देना एक-दूसरे से संबंधित हैं तथा इसलिये, वोट देने की छूट रशिवत पर भी लागू होती है।
  - न्यायालय ने आगे कहा कि एक सांसद जसिने रशिवत ली लेकिन सदन में मतदान से अनुपस्थिति रहा, उसे ऐसी छूट प्रापत नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों** की पीठ ने कहा कि कोई वधायक वधायिका में वोट या भाषण के संबंध में रशिवतखोरी के आरोप में अभियोजन से **अनुच्छेद 105 और 194** के तहत छूट नहीं मांग सकता है।
  - रशिवतखोरी का अपराध तब पूरा होता है जब वधायक रशिवत स्वीकार कर लेता है।

## गृह मामले

### नागरकिता नयिमों में संशोधन अधसूचति

- गृह मंत्रालय ने **नागरकिता (संशोधन) नयिम, 2024** को अधसूचति कयिा।
- यह **नागरकिता (संशोधन) अधनियिम, 2019** के अनुसार नागरकिता के लिये प्रकरयिा प्रदान करने हेतु **नागरकिता नयिम, 2009** में संशोधन करते हैं।
- वर्ष 2019 का संशोधन अधनियिम अफगानसितान, पाकसितान या बांग्लादेश से आए हद्दि, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई या सखि अवैध प्रवासयिों को नागरकिता का पात्र बनाता है।
- इसके लिये यह ज़रूरी है कि उन्होंने 31 दसिंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कयिा हो।
- वर्ष 2024 के नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिन्लखिति शामिल हैं:
  - आवश्यक दस्तावेज़:**
    - आवेदक को अफगानसितान, पाकसितान या बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीयता के कसिी एक प्रमाण की एक प्रतलिपि प्रदान करनी होगी। इनमें **पासपोर्ट, जनम प्रमाण-पत्र**, कसिी भी प्रकार के पहचान दस्तावेज़, **लाइसेंस या भूमि रकिॉर्ड** की प्रतलिपि शामिल है।
    - आवेदक को नरिदषिट दस्तावेज़ों में से कोई भी एक प्रदान करना होगा जो साबति करता है कि उसने 31 दसिंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कयिा था। इनमें भारत में आगमन पर **वीजा** और आवरण टकिट की प्रतलिपि, भारत में जारी **राशन कार्ड**, भारत में पंजीकृत रेंटल एग्रीमेंट, भारत में जारी **बीमा पॉलिसी**, या सरकार या न्यायालय द्वारा आवेदक को आधिकारिक टकिट के साथ जारी कयिा गया कोई पत्र शामिल है।
    - आवेदक को अपने धर्म की घोषणा करते हुए एक पात्रता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसे स्थानीय स्तर पर प्रतषिटति सामुदायिक संस्थान द्वारा प्रमाणित कयिा जाना चाहिये।
  - नागरकिता का सत्यापन और उसे प्रदान करना:**
    - कषेत्राधिकार के वरषिट अधीकषक या डाक अधीकषक की अध्यक्षता में एक ज़िला-स्तरीय समिति, आवेदन का सत्यापन करेगी और नषिटा की शपथ दलाएगी।

- यह प्रासंगिक दस्तावेजों को सत्यापन के लिये किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के जनगणना संचालन नदिशक की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करेगा।
- संतुष्ट होने पर अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को नागरिकता प्रदान करेगी।
- वर्ष 2009 के नियमों के तहत, आवेदन संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाते हैं। वह आवेदन का सत्यापन करता है और फरि इसे राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को भेज देता है।
- इसके बाद आवेदन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जो सभी जाँच पूरी करने के बाद नागरिकता प्रदान करती है।

## कॉर्पोरेट मामले

### भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग ने प्रतबिद्धता और नपिटान नियमों को अधिसूचि कयि

- [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग](#) (Competition Commission of India- CCI) ने [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(प्रतबिद्धता\) वनियम, 2024](#) और [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग \(नपिटान\) वनियम, 2024](#) को अधिसूचि कयि।
- इन वनियमों को [प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002](#) के तहत अधिसूचि कयि गया है, जसि प्रतबिद्धता और नपिटान प्रतबिद्धता ढाँचे के लयि वर्ष 2023 में संशोधति कयि गया था।
- संशोधति अधनियम उद्यमों को कुछ प्रतबिद्धताओं (जैसे- बाज़ार व्यवहार में परिवर्तन) या भुगतान नपिटान की पेशकश करने की अनुमति देता है।

#### वर्ष 2024 वनियमों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- **प्रतबिद्धता:** जाँच शुरू करने के लयि CCI द्वारा पारति आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर CCI के पास एक प्रतबिद्धता आवेदन दाखलि कयि जाना चाहयि।
- पूरी प्रक्रयि प्रतबिद्धता आवेदन की प्राप्त से 130 कार्य दिवसों में पूरी होनी चाहयि।
- प्रस्तावति प्रतबिद्धताओं की प्रभावीता को नमिनलखिति कारकों के आधार पर मापा जाएगा:
  - कथति उल्लंघन की प्रकृति, अवधि और सीमा।
  - यदि प्रतबिद्धता की शर्तें प्रतस्पर्द्धा संबंधी चतिाओं को दूर कर करती हैं।
  - अगर प्रतबिद्धता की शर्तें बाज़ारों को अधिक प्रतस्पर्द्धा बनाती हैं।
- **नपिटान:** कथति उल्लंघनों पर CCI के महानदिशक की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर नपिटान आवेदन कयि जाना चाहयि।
- संपूर्ण प्रक्रयि नपिटान आवेदन प्राप्त होने के 180 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जानी चाहयि। नपिटान राशिका निर्धारण आधार राशिकि 15% की छूट लागू करके कयि जाएगा।

## वति

### स्व-नयामक संगठनों हेतु रूपरेखा

- [भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#) ने वनियमति संस्थाओं के लयि [स्व-नयामक संगठनों \(Self-regulatory Organizations- SRO\)](#) की मान्यता हेतु एक रूपरेखा जारी की।
- RBI की वनियमति संस्थाओं में बैंक, गैर-बैंकिंग वति कंपनीयों और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर शामिल हैं।
- SRO तकनीकी वशिषज्जता और नयामक नीतियों को तैयार करने में मदद करके, नयमों का असर बढ़ा सकते हैं।

#### प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **मान्यता की प्रक्रयि:** कोई इच्छुक SRO मान्यता के लयि **RBI** को आवेदन कर सकता है। इसके लयि उसे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना।
  - कषेत्र का प्रतनिधित्व करना और नरिदषिट सदस्यता होना।
  - इसके नदिशकों के पास पेशेवर कषमता होनी चाहयि और नषिकषता तथा अखंडता की उनकी साख होनी चाहयि।
- **नरिदषिट सदिधांतों का अनुपालन:** एक SRO को:
  - नैतिक और शासन मानकों को नरिधारति करने के लयि सदस्यता समझौतों से अधिकार प्राप्त करना चाहयि।
  - अपने सदस्यों के आचरण के लयि नयम बनाने हेतु उद्देश्यपूर्ण और परामर्शी प्रक्रयिाँ स्थापति करनी चाहयि।
  - अनुपालन संस्कृति में सुधार के लयि मानक वकिसति करना चाहयि।
  - कषेत्र की प्रभावी नगिरानी के लयि नगिरानी वधियिँ होनी हैं।
- **सदस्यों के प्रत जिमिेदारयिँ:** अपने सदस्यों के प्रत SRO की प्राथमकि जिमिेदारी सर्वोत्तम व्यावसायिक पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा।

#### अन्य जिमिेदारयिँ में नमिनलखिति शामिल हैं:

- अपने सदस्यों के लयि आचार संहति तैयार करना और उसके अनुपालन की नगिरानी करना।
- एक समान और गैर-भेदभावपूर्ण सदस्यता शुल्क संरचना वकिसति करना।

- अपने सदस्यों के लिये शिकायत नविवरण और विवाद समाधान/मध्यस्थता ढाँचे की स्थापना करना ।
- वैधानिक/नियामक प्रावधानों की जानकारी को बढ़ावा देना ।
- **सदस्यता के मानदंड:** क्षेत्र का समग्र रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिये SRO के पास सभी स्तरों पर सदस्यों का अच्छा मशिरण होना चाहिये ।
  - सदस्यता मानदंड RBI द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
  - SRO की सदस्यता स्वैच्छिक होगी । SRO को मान्यता प्रदान करने के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम निर्धारित सदस्यता प्राप्त की जानी चाहिये ।

## बीमा उत्पादों के लिये वनियम अधिसूचि

- **भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने **इरडाई (बीमा उत्पाद) वनियम, 2024** को अधिसूचि किया ।
- इसमें कई नियमों को नरिस्त करने का प्रयास किया गया है, जिनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - इरडाई (सूक्ष्म बीमा) वनियम, 2015
  - इरडाई (स्वास्थ्य बीमा) वनियम, 2016
  - इरडाई (यूनटि लकिड इश्योरेंस प्रोडक्ट्स) वनियम, 2019

### मुख्य वशिषताओं में नमिन शामिल हैं:

- **डज़ाइन और मूल्य नरिधारण:**
  - बीमा उत्पादों के डज़ाइन और मूल्य नरिधारण को कुछ मानदंडों का पालन करना चाहिये ।
  - इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
    - ग्राहकों की बढ़ती जोखमि कवरेज ज़रूरतों को सुनिश्चि करना ।
    - समझने में आसान उत्पाद ।
    - प्रीमियम दरें अत्यधिक, अपर्याप्त या भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिये ।
    - उत्पादों का मूल्य नरिधारण करते समय सभी प्रासंगिक जोखमिों को ध्यान में रखना ।
- उत्पाद प्रबंधन समिति: प्रत्येक बीमाकर्त्ता के बोर्ड को एक उत्पाद प्रबंधन समिति का गठन करना होगा ।
- समिति की ज़मिमेदारियों में नमिनलखिति सुनिश्चि करना शामिल है:
  - लक्ष्य बाज़ार के लिये उचित उत्पाद डज़ाइन
  - वनियामक अनुपालन
  - उत्पाद प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा
  - अगर आवश्यक हो, तो उत्पाद में संशोधन या वापसी ।
- उत्पादों की समीक्षा: सभी बीमा उत्पादों की वर्ष में कम-से-कम एक बार नयिकृत बीमांकिक द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये ।
- समीक्षा में नमिनलखिति पर वचिार किया जाना चाहिये:
  - सभी हतिधारकों की उचित अपेक्षाएँ ।
  - उत्पाद की वतितीय व्यवहार्यता ।
  - उत्पाद के तहत उभरता जोखमि और अनुभव ।
  - कोई अन्य प्रासंगिक कारक ।

## सूचकांक प्रदाताओं के लिये नयिम

- **भारतीय प्रतभित और वनियमि बोर्ड** (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने **सेबी (सूचकांक प्रदाता) वनियम, 2024** को अधिसूचि किया ।
- इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - सूचकांक की गणना ।
  - सूचकांक पद्धति का नरिधारण ।
  - सूचकांक का प्रसार ।
- वनियम उन सूचकांक प्रदाताओं पर लागू होंगे जो भारतीय प्रतभित बाज़ार में उपयोग के लिये किसी मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतभितियों के महत्त्वपूर्ण सूचकांकों का प्रबंधन करते हैं ।
- प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - **पंजीकरण:**
    - सूचकांक प्रदाताओं को सेबी के साथ पंजीकृत होना होगा ।
    - मौजूदा सूचकांक प्रदाताओं के पास पंजीकरण के आवेदन के लिये छह महीने का समय होगा ।
    - आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
      - कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नगिमति इकाई
      - न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 25 करोड़ रुपए ।
      - सूचकांक प्रदाता के तौर पर काम करने के लिये आवश्यक बुनयादी ढाँचा और मानव संसाधन ।
  - **नरिक्षण समिति:**
    - सूचकांक प्रदाता को बेंचमार्क नरिधारण प्रक्रिया को नरित्तरि करने के लिये एक नरिक्षण समिति बनानी होगी । समिति में वशिष से संबंधित अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्ती शामिल होंगे ।

- समिति के कार्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - सूचकांक डज़िाइन या गणना पद्धति में बदलाव की आवश्यकता की समीक्षा करना ।
  - नए वित्तीय बेंचमार्क की शुरुआत की नगिरानी करना ।
  - कसिी सूचकांक को बंद करने की प्रकरियाओं की समीक्षा करना ।
- सूचकांक की गुणवत्ता:
  - सूचकांक डज़िाइन को अंतरनहिति हति का प्रतनिधितिव करना चाहयि जसि सूचकांक मापने का प्रयास कर रहा है ।
  - सूचकांक की गणना उस डेटा का उपयोग करके की जानी चाहयि जो अंतरनहिति ब्याज का प्रतनिधितिव करने के लयि पर्याप्त है ।
  - डेटा इनपुट और डेटा के उपयोग के तरीके से संबंधति दशिा-नरिदेश सार्वजनकि डोमेन में उपलब्ध होने चाहयि ।
- वविाद नविराण: सूचकांक प्रदाता को सूचकांक प्रदाता और ग्राहकों के बीच वविादों के लयि एक वविाद समाधान तंत्र बनाना होगा ।

## लघु और मध्यम REIT के लयि रूपरेखा

- भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने सेबी (रयिल एस्टेट नविश ट्रस्ट) वनियमि, 2014 में संशोधनों को अधसूचति कयि है ।
- रयिल एस्टेट नविश ट्रस्ट (REIT) रयिल एस्टेट परसिंपत्तयिों में नविश करने के लयि नविशकों से धन एकत्र करते हैं ।
- वर्ष 2024 के संशोधनों के तहत प्रमुख परविरतनों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - REIT की परभाषा:
    - वर्ष 2014 के वनियमि REIT को वनियमिों के तहत पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में परभाषति करते हैं ।
    - वर्ष 2024 का संशोधन नरिदषित करता है कि REIT एक ऐसे व्यक्तिको कहा जाता है जो रयिल एस्टेट परसिंपत्तयिों या संपत्तयिों को हासलि और प्रबंधति करने के लयि कम-से-कम 200 नविशकों से कम-से-कम 50 करोड रुपए एकत्र करता है । इससे नविशकों को प्रबंधन नयितरण दयि बिना ऐसी परसिंपत्तयिों से उत्पन्न आय प्राप्त करने का अधिकार मलि जाएगा ।
  - लघु और मध्यम REIT:
    - लघु और मध्यम REIT योजना के तहत हासलि की जा सकने वाली संपत्ति का मूल्य 50 करोड रुपए से 500 करोड रुपए के बीच होगा ।
    - REIT के नविश प्रबंधक, उसके संबंधति पक्षों और सहयोगयिों को छोडकर, इसमें कम-से-कम 200 यूनटिधारक होने चाहयि ।
  - पात्रता:
    - पंजीकरण के लयि लघु और मध्यम REIT को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे:
      - ट्रस्ट की ओर से नविश प्रबंधक द्वारा कयि जा रहा पंजीकरण आवेदन
      - नविश प्रबंधक के पास कम-से-कम 20 करोड रुपए की शुद्ध संपत्ति और रयिल एस्टेट उद्योग या रयिल एस्टेट फंड प्रबंधन में कम-से-कम दो वर्ष का अनुभव
      - नविश प्रबंधक के कम-से-कम आधे नदिशक स्वतंत्र ।

## उद्योग

### इलेक्ट्रकि वाहनों के घरेलू वनिरिमाण को बढावा देने की योजना

- भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रकि यात्री कारों की वनिरिमाण को बढावा देने की योजना को अधसूचति कयि है ।
- यह योजना वैश्वकि नरिमाताओं को इलेक्ट्रकि वाहनों (EV) पर कम आयात शुल्क की पेशकश करेगी, बशरते कि नरिमाता घरेलू मैनुफैक्चरकि के लयि प्रतबिद्ध हों ।
- योजना की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - पात्रता:
    - यह योजना न्यूनतम 10,000 करोड रुपए के वार्षकि राजस्व वाले वैश्वकि ऑटोमोटिव नरिमाताओं के लयि खुली है ।
    - नरिमाता को भारत में EV के नरिमाण के लयि तीन वर्ष की अवधि में कम-से-कम 4,150 करोड रुपए (500 मलियन USD) का नविश करने के लयि प्रतबिद्ध होना चाहयि ।
    - नरिमाता को अनुमोदन के तीन वर्षों के भीतर 25% घरेलू मूल्यवर्धन और पाँच वर्षों के भीतर 50% हासलि करना होगा ।
  - प्रोत्साहन:
    - यह योजना नरिमाताओं को अनुमोदन की तारीख से पाँच वर्ष के लयि पूरी तरह से आयातति EV पर 15% के कम आयात शुल्क की पेशकश करती है ।
    - आयातति EV का न्यूनतम लागत, बीमा और माल ढुलाई (CIF) मूल्य 35,000 USD होना चाहयि ।
  - बैंक गारंटी:
    - नरिमाता को 4,150 करोड रुपए की बैंक गारंटी या छोडे गए शुल्क की मात्रा, जो भी अधिक हो, जमा करने की आवश्यकता होगी ।

### इलेक्ट्रकि मोबलिटी प्रमोशन योजना

- भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रकि मोबलिटी प्रमोशन योजना, 2024 को अधसूचति कयि है ।
- इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रकि दो और तीन-पहयिा वाहनों (ई-रकिशा सहति) को तेज़ी से अपनाने को बढावा देना है ।
- इसका परवियय 500 करोड रुपए होगा । इसे अप्रैल और जुलाई 2024 के बीच चार महीनों में लागू कयि जाएगा ।
- प्रमुख वशिषताओं में शामिल हैं:

- **उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन:**
  - दोपहिया और तपिहिया के लिये 5,000 रुपए प्रति kWh का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  - यह योजना मुख्य रूप से वाणज्यिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहनों को कवर करेगी।
  - हालाँकि निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले दोपहिया EV को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 
- **प्रोत्साहनों का दावा:**
  - सरकार से प्रोत्साहन का दावा करने के लिये नरिमाताओं को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।
  - इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
    - भारी उद्योग मंत्रालय के साथ पंजीकरण और उनके प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल के लिये अनुमोदन।
    - प्रत्येक वाहन मॉडल प्रदर्शन और दक्षता के लिये न्यूनतम तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
    - वाहन का नरिमाण भारत में कया जाना चाहिये।

## पर्यावरण

### प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने [प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016](#) में संशोधन अधिसूचति कया है। संशोधन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के नरिमाताओं के लिये दायित्व नरिधारति करते हैं।
- संशोधनों की मुख्य वशिषताओं में नमिन शामिल हैं:
- **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के नरिमाता:**
  - ऐसे प्लास्टिक पर भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी अलग-अलग चहिन एवं लेबल होने चाहिये।
  - कंपोस्टेबल/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादों के नरिमाताओं को वपिणन या बकिरी से पहले [केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड](#) (Central Pollution Control Board- CPCB) से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- **EPR पूरा करने हेतु बाध्य संस्थाएँ:**
  - प्लास्टिक उत्पादों के वकिरेताओं और नरिमाताओं को वसितारति उत्पादक जमिमेदारी (EPR) दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है।
  - वर्ष 2016 के नयिमों के तहत, बाध्य संस्थाओं में प्लास्टिक पैकेजिंग के नरिमाता शामिल थे।
  - संशोधनों से MSME उत्पादकों को छूट मिलती है। MSME के कुछ दायित्वों को उनके कच्चे माल के आपूर्तकिरत्ताओं द्वारा पूरा कया जाएगा।
  - हालाँकि MSME को पुनरनवीनीकृत प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करना होगा।
- **EPR प्रमाण-पत्रों का व्यापार:**
  - नयिम EPR प्रमाण-पत्रों के व्यापार की अनुमतिते हैं।
  - संशोधन नरिदष्टि करते हैं कि प्रमाण-पत्र की कीमत कुछ सीमाओं के अधीन CPCB द्वारा नरिधारति की जाएगी।
  - न्यूनतम कीमत गैर-अनुपालन संस्थाओं द्वारा देय मुआवज़े का 30% होगी और अधिकतम कीमत मुआवज़े का 100% होगी।
- **एकल उपयोग प्लास्टिक हेतु कच्चा माल:**
  - संशोधन प्लास्टिक के कच्चे माल के नरिमाताओं और आयातकों को उन संस्थाओं को आपूर्तकिरने से रोकते हैं जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का नरिमाण करती हैं जो कानून द्वारा नषिदिध हैं।

### बैटरी अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2022

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने [बैटरी अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2022](#) में संशोधन को अधिसूचति कया।
- नयिमों के अनुसार बैटरी उत्पादकों को बैटरी अपशष्टि के पुनरचकरण और नवीनीकरण से संबंधित [वसितारति नरिमाता जमिमेदारी \(EPR\)](#) दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- EPR दायित्वों को पूरा करने के लिये EPR प्रमाण-पत्रों का व्यापार कया जा सकता है।
- संशोधनों की मुख्य वशिषताएँ हैं:
  - **EPR प्रमाण-पत्रों का मूल्य:**
    - [केंद्रीय प्रदूषण नयित्रण बोर्ड \(CPCB\)](#) को EPR प्रमाण-पत्रों के लिये न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य नरिदष्टि करना होगा।
    - मूल्य को संग्रह की लागत, पर्यावरणीय क्षतपूरति और अपशष्टि बैटरियों के अच्छे प्रबंधन में शामिल कया जाना चाहिये।
    - संशोधनों के अनुसार, EPR प्रमाण-पत्र की न्यूनतम कीमत मुआवज़े का 30% होगी और अधिकतम कीमत मुआवज़े का 100% होगी।
  - **मुआवज़े पर दशा-नरिदेश:**
    - वर्ष 2022 के नयिमों के तहत CPCB को EPR दायित्वों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवज़ा वसूलने का अधिकार है।
    - वर्ष 2024 के संशोधनों के अनुसार, CPCB दशा-नरिदेश तैयार करेगा और सुझाव देगा। प्रकरया के दौरान CPCB कार्यान्वयन समिति से परामर्श कर सकता है।

## स्वास्थ्य

## उन्नयन सहायता योजना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने संशोधित फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। संशोधित योजना की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **एप्लिकेबिलिटी बढ़ाई गई:**
  - मूल योजना के तहत, MSME को नयामक मानकों को पूरा करने के लिये ब्याज छूट प्रदान की गई थी।
  - संशोधित योजना में फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग इकाइयों को शामिल करने के लिये पात्रता का वसतिार कथिा गया है, जसिमें वे इकाइयों भी शामिल हैं जनिा औसत तीन साल का कारोबार 500 करोड़ रुपए से कम है।
- **नए मानकों के अनुपालन के लिये समर्थन:**
  - मूल योजना के तहत हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनगि (HVAC) ससि्टम, सथरिा परीक्षण कक्ष तथा स्रेराइल एरयिाज़ के लिये सवचालति पारटकिल काउंटर जैसे अपगरेडेशन के लिये सहायता प्रदान की गई थी।
  - इन उन्नयनों के लिये सपोर्ट के अलावा, संशोधित योजना में सवच्छ कमरे की सुवधिाएँ, अपशषि्ट उपचार और पानी तथा भाप उपयोगतिाएँ शामिल होंगी।
- **टर्नओवर आधारति प्रोत्साहन संरचना:**
  - प्रोत्साहन की गणना वासतवकि नविश के प्रतशित के रूप में की जाएगी।
  - इसे पछिले तीन वर्षों के औसत टर्नओवर से भी जोड़ा जाएगा।

## नवीन एवं अक्षय ऊर्जा

### राष्ट्रीय हरति हाइडरोजन मशिन

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने [राष्ट्रीय हरति हाइडरोजन मशिन](#) के तहत वभिनिन योजनाओं के लिये दशिा-नरिदेश जारी कथिे हैं।
- मशिन के अंतरगत योजनाओं में शामिल हैं:
  - अनुसंधान एवं वकिस (R&D)।
  - इलेक्ट्रोलाइज़र वनरिमाण के लिये प्रोत्साहन (पानी को हाइडरोजन और ऑक्सीजन में परविरतति करने वाला एक उपकरण)।
  - कौशल वकिस।
  - हाइडरोजन हब की सथापना।
- **अनुसंधान एवं वकिस योजना:**
  - हाइडरोजन उत्पादन, स्टोरेज, परीक्षण और परविहन जैसे क्शेत्रों में अनुसंधान एवं वकिस के लिये वततिीय सहायता (परयिोजना की लागत के लिये) प्रदान की जाएगी।
  - मौजूदा क्शमताओं के आधार पर परयिोजनाओं को अलपावधि (पाँच वर्ष तक), मध्यावधि (आठ वर्ष तक) और दीर्घावधि (15 वर्ष तक) में वभिजति कथिा जाएगा।
- **इलेक्ट्रोलाइज़र नरिमाण:**
  - यह योजना इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू वनरिमाण को समर्थन देने के लिये वततिीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  - पात्र होने के लिये कंपनयिों की प्रतर्ता भेगावाट वनरिमाण क्शमता का शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए होना चाहयिे।
  - छोटे नरिमाता (30 लाख रुपए प्रतर्ता भेगावाट या उससे अधकि की कुल संपततिवाले) भी योजना की एक अलग कशित के तहत पात्र हैं।
- **हाइडरोजन हब की सथापना:**
  - ऐसे क्शेत्र जो हाइडरोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन/उपयोग का समर्थन कर सकते हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें हाइडरोजन हब के रूप में वकिसति कथिा जाएगा।
  - भंडारण और परविहन तथा जल उपचार सुवधिाओं जैसे मुख्य बुनयिादी ढाँचे के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।
- **कौशल वकिस:**
  - इस योजना का उद्देश्य स्कूलों और उच्च शकिसण संसथानों के लिये कौशल वकिस तथा पाठ्यक्रम डज़ाइन करना है।
  - 18-45 वर्ष की आयु के व्यकति, जो आवश्यक नौकरी मानदंडों को पूरा करते हैं, प्रशकिसण के लिये पात्र होंगे।

## वाणजिय

### उत्तर पूर्व परविरतनकारी औद्योगीकरण योजना

- केंद्रीय मंत्रमिंडल ने उत्तर पूर्व परविरतनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नतति), 2024 को मंजूरी दी है।
- केंद्रीय क्शेत्र की योजना 10 वर्ष की अवधि में 10,037 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ लागू की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में उद्योगों का वकिस करना और रोजगार पैदा करना है।
- योजना के तहत प्रदान कथिे जाने वाले प्रोत्साहनों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - नई और वसितारति इकाइयों के लिये पूंजी नविश प्रोत्साहन।
  - नई और वसितारति इकाइयों के लिये ब्याज छूट।
  - नई इकाइयों के लिये मैनुफैक्चरगि से जुड़े प्रोत्साहन।

# यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association- EFTA) के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- EFTA में स्वटिज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लकितेंस्टीन शामिल हैं।
- समझौते के तहत, EFTA का लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष वदेशी निवेश को 100 बिलियन USD तक बढ़ाना होगा।
- EFTA में भारत को सभी गैर-कृषि उत्पादों को कवर करने वाली बाजार पहुँच और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायत मिलेगी।
- भारत लोहे और इस्पात की कुछ वस्तुओं, कपड़ों तथा भवन निर्माण मशीनरी जैसे सामानों पर टैरिफ रियायतें प्रदान करेगा।

## कोयला

### अंतर-मंत्रालयी समिति ने कोयला आयात प्रतस्थापन पर रपिर्ट जारी की

- कोयला मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कोयला आयात प्रतस्थापन पर एक रपिर्ट जारी की।
- कोयले का उपयोग बड़े पैमाने पर बजिली उत्पादन (64%), इस्पात उत्पादन (8%) और सीमेंट उत्पादन (5%) के लिये किया जाता है।
- वर्ष 2030 तक कोयले की मांग 1.6 बिलियन टन होने का अनुमान है।
- प्रमुख टपिपणियों और अनुशंसाओं में शामिल हैं:
  - **कोकगि कोल के आयात में कमी:**
    - कोकगि कोल का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। इस्पात उद्योग अपने कोकगि कोल की 90% आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
    - इस प्रकार, समिति ने सफिराशि की कि इस्पात क्षेत्र को अधिक कोकगि कोयले की आपूर्ति की जानी चाहिये।
    - समिति ने यह भी सफिराशि की कि धुलाई क्षमता बढ़ाई जाए।
  - **गैर-कोकगि कोल आयात में कमी:**
    - नॉन-कोकगि कोल का उपयोग बजिली उत्पादन में किया जाता है।
    - समिति ने सुझाव दिया कि बॉयलर घरेलू कोयले का उपयोग करें और उन्हें घरेलू कोयले के अनुकूल बनाने के लिये रेट्रोफिट किया जाए।
  - **कोयले पर GST क्षतपूरति उपकर:**
    - 400 रुपए प्रततिन की दर से उपकर लगाया जाता है। यह मूल (घरेलू या आयातित), गुणवत्ता या स्रोत की परवाह किये बिना है।
    - इससे ऊर्जा की प्रतियुनटि घरेलू कोयले की लागत अधिक हो जाती है, क्योंकि आयातित कोयले की तुलना में घरेलू कोयला आमतौर पर ऊर्जा सामग्री में कम होता है।
    - समिति ने कोयले पर GST क्षतपूरति उपकर को तर्कसंगत बनाने की सफिराशि की।